



गुरुवाणी

“मानसिक विकार, जैसे निराशा, चिंता आदि में रहने से पाचन तंत्र कमजोर होता है।”

गुनि श्री वीरसागर जी महाराज

स्वस्थ मन ही स्वस्थ पाचन का आधार है।

शरीर का स्वास्थ्य जीवन

शरीर का स्वास्थ्य जीवन

शरीर का स्वास्थ्य जीवन



दैनिक हिन्दी समाचार प्रवेण

हिन्दी सागर

प्रवेण लोकतन्त्र का

जनसूचना से जनजागरण

आम आदमी का मीडिया मंच



BIKANERVALA

Sweets / Fine Dining / Party Hall / Outdoor Catering

Delicious Tastes, Elegant Ambiance & Premium Service - All at Affordable Prices

JAYANAGAR - BENGALURU



80000 30000 20000 10000 0

एनएलएसआईयू विस्तार के लिए कर्नाटक सरकार प्रतिबद्ध: CM शिवकुमार

बेंगलुरु में एनएलएसआईयूके विस्तार के लिए भूमि और वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई

► **कर्नाटक ब्यूरो** बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ ​​इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के विस्तार के लिए कर्नाटक सरकार पूरी तरह से समर्थन देगी। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आश्वासन दिया है कि कानून की शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए न केवल आवश्यक भूमि आवंटित की जाएगी, बल्कि वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सात एकड़ या 10 एकड़, जितनी भी भूमि की आवश्यकता होगी, उसे आवंटित करने और आर्थिक मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने बेंगलुरु के ज्ञानभारती परिसर में



एनएलएसआईयूके दक्षिण ब्लॉक, सभागार और छात्र केंद्र के निर्माण के लिए शनिवार को भूमि पूजन के बाद यह घोषणा की। इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजु बखर भी मौजूद थे। शिवकुमार ने कहा कि राज्य में नेशनल लॉ स्कूल की स्थापना में कर्नाटक का अग्रणी होना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने याद

उन्की टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित संस्थान की रक्षा करना और इसे विकसित करना सरकार की जिम्मेदारी है। शिवकुमार ने विश्वास व्यक्त किया कि यह विस्तार भविष्य के नेताओं को तैयार करने में सहायक होगा, जो लोकतंत्र को मजबूत करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विस्तार के प्रयासों के लिए उप-कुलपति प्रो. सुधीर कृष्णस्वामी और

जिस पर सरकार मुख्य न्यायाधीशों के अनुरोध पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्दोंी जनरल का कार्यालय एक ऐतिहासिक इमारत है, और देश में विधायिका के सामने न्यायपालिका का यह एकमात्र स्थान है। उन्होंने कहा कि सरकार एक और ऐतिहासिक इमारत का निर्माण करना चाहती है और इस दिशा में काम कर रही है। इस महीने के अंत तक मंत्रिमंडल में इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यह भी जानकारी सामने आई कि बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ ​​इंडिया यूनिवर्सिटी की एक पूर्व छात्रा कनाडा में फैमिली कोर्ट जज के रूप में नियुक्त हुई है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि प्रस्तावित न्यायिक बुनियादी ढांचा और NLSIU परिसर का विस्तार, दोनों लोकतांत्रिक संस्थाओं और कानूनी शिक्षा को मजबूत करने में एक-दूसरे के पूरक होंगे। इसलिए, संस्थान की स्थापना के बाद के विकास के अनुरूप अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना उनका कर्तव्य है।

जाति रिपोर्ट लागू करो, वरना प्रदर्शन

कर्नाटक सरकार को एक सप्ताह में रिपोर्ट लागू करने की मोहलत

कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग महासंघ ने राज्य सरकार को सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण (जाति जनगणना) रिपोर्ट लागू करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है। महासंघ के अध्यक्ष के एम रामचंद्रप्पा ने शुक्रवार को कहा कि ऐसा न करने पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, लोकसभा में विधु के नेता राहुल गांधी और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। रामचंद्रप्पा ने मांग की कि इस मुद्दे पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाए और सिद्धरामैया के कार्यकाल के दौरान जारी आदेश को तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया और बताया कि सर्वेक्षण पर लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले जारी 97 करोड़ रुपये के अनुदान को भी रोक दिया है।

कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हर विरोध को देगी आर्थिक मदद: हरिप्रसाद

► **धारवाड़ ब्यूरो** धारवाड़: संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'काक्रोश जनता पार्टी' (सीजेपी) और अन्य प्रदर्शनों को कांग्रेस पार्टी आर्थिक सहायता देगी, ऐसा बीके हरिप्रसाद ने शनिवार को कहा। हरिप्रसाद ने कहा कि यह हमारा अधिकार है, और जो कोई भी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है, वह सीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किसी भी विरोध प्रदर्शन को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के उन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी कि कर्नाटक सरकार दिल्ली में सीजेपी विरोध प्रदर्शनों को वित्तीय सहायता दे रही है। कुमारस्वामी ने मांग की थी कि सीजेपी और कांग्रेस एक ही हैं, और सीजेपी दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के लिए कर्नाटक से धन प्राप्त कर रही है, इसे सार्वजनिक किया जाए।

कर्नाटक में आईएनडीआईए गठबंधन की समन्वय समिति का पठन, मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ आंदोलन की घोषणा

► **कर्नाटक प्रतिनिधि** कर्नाटक में आईएनडीआईए गठबंधन के दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक राज्य-स्तरीय समन्वय समिति बनाने का फैसला किया है। दलों का आरोप है कि यह प्रक्रिया योग्य मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकती है। यह निर्णय बेंगलुरु में विधायक भवन में आयोजित आईएनडीआईए गठबंधन के घटकों की राज्य-स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में तय हुआ कि दल 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़े विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे और उसके बाद कर्नाटक में अपना आंदोलन तेज करेंगे। केपीसीसी अध्यक्ष बी के हरिप्रसाद ने एक्स पर एक पोस्ट में इन निर्णयों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दल संविधान, लोकतंत्र और मतदान के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट संघर्ष शुरू करने पर सहमत हुए हैं। बैठक में सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई(ML) लिबरेशन, समाजवादी पार और फॉरवर्ड ब्लॉक के राज्य नेताओं के साथ कांग्रेस प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेताओं ने SIR प्रक्रिया के खिलाफ जनमत तैयार करने और राज्य भर में विरोध प्रदर्शनों का समन्वय करने की रणनीतियों पर चर्चा की।

कब्बू की लाभकारी कीमत की मांग पर बेलगावी में किसानों का प्रदर्शन

कब्बू के लिए ₹ 5,500 समर्थन मूल्य की मांग, किसानों ने वन्रम्मा सर्कल पर किया प्रदर्शन

► **बेलगावी ब्यूरो** बेलगावी में कब्बू की लाभकारी कीमत की मांग को लेकर कर्नाटक राज्य किसान संघ और हरित सेना (कोडिहल्ली चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को चन्नम्मा सर्कल पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने रानी चन्नम्मा सर्कल पर दो घंटे तक मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शनकारियों ने 2026-27 सीजन के लिए कब्बू पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर में संशोधन करने और कब्बू उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मजदूरी और आवश्यक वस्तुओं की लागत दोगुनी हो गई है, इसलिए केंद्र सरकार को एफआरपी तय करनी चाहिए। साथ ही, राज्य सरकार को सहायता राशि देकर उचित मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कोडिहल्ली चंद्रशेखर ने कहा कि फसल क्षति से किसान त्रस्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि



उन्होंने कहा कि विश्वसनीय बिजली आपूर्ति कृषि गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है और वर्तमान स्थिति किसानों

सरकार लगातार सिंगल-फेस बिजली प्रदान करने और बिजली आपूर्ति में विफल रही है। उन्होंने तत्काल उचित बिजली आपूर्ति की मांग की। किसानों ने कहा कि फसल

बीमा भरने के बावजूद उन्हें फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिल रहा है। उन्होंने सुअरों और जंगली जानवरों से फसल क्षति को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का

भी आग्रह किया। किसानों ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार द्वारा सूखा घोषित किए जाने के बावजूद, किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है।

एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम: 3 साल में 6,994 मामले, सिर्फ 111 को सजा

► **बेंगलुरु प्रतिनिधि** दलित समुदाय को उपरीइन से बचाने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू है। इस कानून के तहत पिछले तीन वर्षों में 6,994 मामले दर्ज किए गए हैं। जातिगत अपमान सहित विभिन्न जिलों में दलितों के खिलाफ उपरीइन के आरोपों के तहत ये मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि, सजा पाए मामलों की संख्या बहुत कम है। सरकार के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। 2024 में इस कानून के तहत 2483 मामले दर्ज हुए, जबकि 2025 में 2678 और 2026 में 1833 मामले दर्ज किए गए। इसके बावजूद, सजा पाए मामलों की संख्या केवल 111 है। यह सवाल उठता है कि बाकी मामलों का क्या हुआ। 2024 में 2483 मामले दर्ज हुए, 2025 में 2678 मामले दर्ज हुए और 2026 में 1833 मामले दर्ज हुए। इन वर्षों में दर्ज हुए कुल मामलों में से केवल 681 मामलों में ही बी और सी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। 1774 मामले वर्तमान में अदालत की जांच के अधीन हैं।

कुमारस्वामी का आरोप: राजनीतिक नेतृत्व को नियंत्रण में रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा स्टिंग वीडियो

► **बेंगलुरु शहरी ब्यूरो** केंद्रीय मंत्री और जद (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक में राजनीतिक नेतृत्व को नियंत्रण में रखने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने जद (एस) नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी की अगली रणनीति तय की जाएगी, जिसमें राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन भी शामिल हो सकते हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि वह पहली बार अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के बारे में भी संदेह जता रहे हैं कि वह भी स्टिंग ऑपरेशन का शिकार हो सकते हैं। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब स्टिंग ऑपरेशन के कथित मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई के लिए कुमारस्वामी द्वारा बेंगलुरु पुलिस आयुक्त को दी गई दो दिन की समय सीमा शनिवार को समाप्त हो गई। लोक भवन में नए राज्यपाल सुधा यादव



से शिष्टाचार भेंट करने के फ़ाद पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि पार्टी अपने नेताओं की राय पर विचार करने के बाद अपना अगला कदम तय करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जद (एस) व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण नहीं,

बल्कि कर्नाटक के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के कारण यह मुद्दा उठा रही है। उन्होंने कुमारस्वामी ने आरोप लगाया, “हम ऐसी स्थिति के गवाह बन रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य को कठपुतली बनाया जा रहा है। ” उन्होंने

सुझाव दिया कि वीडियो का इस्तेमाल राज्य के राजनीतिक नेतृत्व को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। कुमारस्वामी ने कहा कि ऐसी गतिविधियों को समाप्त होना चाहिए, और आरोप लगाया कि मीडिया संगठनों के नामों का दुरुपयोग किया जा रहा है और पत्रकारिता को बदनाम किया जा रहा है। कर्नाटक के मीडिया में उच्च मानक स्थापित करने वाले पत्रकारों और संपादकों के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता बहाल करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार में इस मुद्दे को संबोधित करने की इच्छाशक्ति की कमी है, और दावा किया कि इसे चलाने वाले लोग सी पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया संगठनों के नामों का दुरुपयोग किया जा रहा है और पत्रकारिता को बदनाम किया जा रहा है।

► **बेंगलुरु शहरी ब्यूरो** कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र वह नहीं है जहाँ हर कोई सरकार से सहमत हो, बल्कि वह है जहाँ हर नागरिक को सत्ता में बैठे लोगों पर सवाल उठाने की बुनियादी स्वतंत्रता हो। उन्होंने बेंगलुरु में राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएलएसआईयू) के 34वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। शिवकुमार ने इस अवसर पर घोषणा की कि राज्य सरकार न्यायिक सेवा के उम्मीदवारों के लिए बेंगलुरु में एक समर्पित कोचिंग संस्थान और परिसर स्थापित करने की योजना बना रही है। यह संस्थान रैसकोर्स परिसर में खोला जाएगा, जिससे योग्य उम्मीदवारों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा।

विदेशी धन से भारत के खिलाफ साजिश: बोम्बई ने केंद्र को चेताया

एनजीओ को मिल रहे विदेशी फंड पर जताई चिंता

► **कर्नाटक रिपोर्टर** पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बसवराज बोम्बई ने कहा है कि भारत के खिलाफ विदेशी धन का उपयोग करके रबी जा रही साजिशों पर केंद्र सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और ऐसी गतिविधियों को पूरी तरह से रोकना चाहिए। हुबली में मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ साजिशों और विदेशी स्रोतों से एनजीओ को मिलने वाले धन के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठन विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त कर रहे हैं। यह साबित हो चुका है कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में विदेशी दान प्राप्त हुआ है।

विशेष रूप से, सोरोस फाउंडेशन जैसे संगठनों से हुबली में मीडिया से बात करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बसवराज बोम्बई ने राज्य सरकार से किसानों के हितों की रक्षा के लिए जल्द से जल्द उचित कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि गन्ने के किसानों के एमएसपी और सुरक्षा के लिए गठित समिति की सोमवार को बैठक होगी। इस बैठक में सभी किसान नेताओं को बुलाकर चर्चा की जाएगी और एक सप्ताह के भीतर उचित समाधान तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार का एक बड़ा योगदान है और जिम्मेदारी है कि वह किसानों की समस्याओं का समाधान करे, क्योंकि सेल टैक्स और जीएसटी के माध्यम से राज्य को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। गन्ने के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द से जल्द एसएपी लागू किया जाना चाहिए।



पिछले 10 वर्षों से धन आ रहा है, यह सिद्ध हो चुका है। राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए बोम्बई ने कहा कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वे देश के खिलाफ बोलते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है।

हुबली में मीडिया से बात करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बसवराज बोम्बई ने राज्य सरकार से किसानों के हितों की रक्षा के लिए जल्द से जल्द उचित कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि गन्ने के किसानों के एमएसपी और सुरक्षा के लिए गठित समिति की सोमवार को बैठक होगी। इस बैठक में सभी किसान नेताओं को बुलाकर चर्चा की जाएगी और एक सप्ताह के भीतर उचित समाधान तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार का एक बड़ा योगदान है और जिम्मेदारी है कि वह किसानों की समस्याओं का समाधान करे, क्योंकि सेल टैक्स और जीएसटी के माध्यम से राज्य को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। गन्ने के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द से जल्द एसएपी लागू किया जाना चाहिए।

स्टिंग ऑपरेशन की जांच हो, दोषी सामने आए: विजयेन्द्र

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेन्द्र ने चित्रदुर्ग में कहा कि स्टिंग ऑपरेशन मामले में मुख्यमंत्री ने स्वयं कैबिनेट बैठक में खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए और दोषियों को सामने लाया जाना चाहिए। विजयेन्द्र ने प्रियंका खरगे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के पीछे कौन है, यह पूरा राज्य जानता है। उन्होंने मांग की कि इसमें चाहे कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों न शामिल हो, उसे बेनकाब किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव समाप्त होने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। विजयेन्द्र ने गात्रा किसानों के आंदोलन और पदयात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को प्रति विवैल एसएपी पर एक हजार रुपये देने चाहिए।

शिवकुमार: मजबूत लोकतंत्र में सवाल पूछने की स्वतंत्रता जरूरी

► **बेंगलुरु शहरी ब्यूरो** कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र वह नहीं है जहाँ हर कोई सरकार से सहमत हो, बल्कि वह है जहाँ हर नागरिक को सत्ता में बैठे लोगों पर सवाल उठाने की बुनियादी स्वतंत्रता हो। उन्होंने बेंगलुरु में राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएलएसआईयू) के 34वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। शिवकुमार ने इस अवसर पर घोषणा की कि राज्य सरकार न्यायिक सेवा के उम्मीदवारों के लिए बेंगलुरु में एक समर्पित कोचिंग संस्थान और परिसर स्थापित करने की योजना बना रही है। यह संस्थान रैसकोर्स परिसर में खोला जाएगा, जिससे योग्य उम्मीदवारों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा।



लिए बेंगलुरु में एक समर्पित कोचिंग संस्थान और परिसर स्थापित करने की योजना बना रही है। यह संस्थान रैसकोर्स परिसर में खोला जाएगा, जिससे योग्य उम्मीदवारों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा।



औद्योगिक क्षेत्रों में भी हो सकता है। भारत में, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और तिरुपति जिलों में ग्रीन अमोनिया उत्पादन से जुड़ी परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। ग्रीन अमोनिया का उत्पादन मुख्य रूप से सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करके किया जाता है। इस प्रक्रिया में, पानी से हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है और हवा से नाइट्रोजन लेकर हैबर-बोश प्रक्रिया के माध्यम से अमोनिया का निर्माण किया जाता है। इसके विपरीत, पारंपरिक अमोनिया उत्पादन में मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ग्रीन अमोनिया उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जो इसे पर्यावरण के लिए एक बेहतर विकल्प बनाता है। ग्रीन अमोनिया का सबसे प्रमुख उपयोग नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के निर्माण में हो सकता है, जो खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, इसे जहाजों के लिए एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में, बिजली उत्पादन के लिए और ऊर्जा भंडारण के एक माध्यम के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। हाइड्रोजन की तुलना में, कुछ परिस्थितियों में अमोनिया का भंडारण और परिवहन अधिक सुविधाजनक हो सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि

अमोनिया विषैली होती है, इसलिए इसके सुरक्षित भंडारण और उपयोग के लिए विशेष व्यवस्थाएं और कड़े सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक है। इन सुरक्षा चिंताओं के बावजूद, ग्रीन अमोनिया की क्षमता ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने की है। आंध्र प्रदेश में

ग्रीन अमोनिया उत्पादन से जुड़ी कई परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण परियोजना आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एएम ग्रीन द्वारा विकसित की जा रही है। इस परियोजना के तहत, मौजूदा औद्योगिक संयंत्रों को ग्रीन अमोनिया उत्पादन के अनुकूल बनाने की योजना है, जिससे वे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग की ओर बढ़ सकें। यह कदम न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा बल्कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी मदद करेगा। यह पहल भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इसके अतिरिक्त, तिरुपति जिले के चिल्लिकुर और कोटा मंडलों में यमनाको की एक और परियोजना विकसित की जा रही है। इस परियोजना का रणनीतिक स्थान कृष्णापट्टनम बंदरगाह के निकट होना इसे परिवहन और निर्यात के लिहाज से विशेष रूप से लाभदायक बनाता है। बंदरगाह के पास होने से कच्चे माल की आवाजाही और तैयार उत्पाद के निर्यात में आसानी होगी, जिससे परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ेगी। यह परियोजना क्षेत्र में ग्रीन अमोनिया के उत्पादन और निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ग्रीन अमोनिया का विस्तार भारत में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है। यह उर्वरक उद्योग में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

270 करोड़ की ड्रग्स बरामदगी: टीवीके नेता की गिरफ्तारी पर स्टालिन ने उठाए चेन्नई में 135 किलो ड्रग्स जब्त



► **न्यूज प्रतिनिधि** चेन्नई। तमिलनाडु में 270 करोड़ रुपये मूल्य की 135 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की बरामदगी के मामले में तमिलनाा वेन्नी कड्गम (टीवीके) के नागपट्टिनम जिला पदाधिकारी ब्रूबलन को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एवं डीएमके नेता एमके स्टालिन ने टीवीके पर सवाल उठाते हुए पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच की मांग की है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने नागपट्टिनम जिले में कई स्थानों पर तलाशी के दौरान नशीले पदार्थों की खेप जब्त की। मामले में अन्य तीन लोगों को भी पृष्ठताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि नशीले पदार्थ कहाँ से लाए गए थे और इन्हें कहाँ पहुंचाया जाना था। कथित तौर पर यह खेप श्रीलंका भेजी जानी थी। स्टालिन ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी खेप से जुड़े मामले में आरोपी व्यक्ति को पार्टी में संगठनात्मक जिम्मेदारी कैसे मिली। वहीं, टीवीके के जिला सचिव एम। सुकुमारन ने बताया कि ब्रूबलन को पार्टी के सभी पदों और जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। मामले में आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच जारी है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की टीम

ने गुप्त सूचना के आधार पर नागपट्टिनम जिले में कई ठिकानों पर एक साथ छापीमारी की। इस दौरान टीम ने 135 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त की, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 270 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह बरामदगी तमिलनाडु में अब तक की सबसे बड़ी नशीले पदार्थों की खेपों में से एक है। अधिकारियों ने मौके से ब्रूलन को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह खेप श्रीलंका भेजी जानी थी, जहां इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जाना था। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि तमिलनाा वेन्नी कड्गम (टीवीके) के नागपट्टिनम जिला पदाधिकारी ब्रूबलन की गिरफ्तारी बेहद चिंताजनक है। स्टालिन ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी से जुड़े आरोपी व्यक्ति को पार्टी में संगठनात्मक जिम्मेदारी कैसे सौंपी गई। उन्होंने इस पूरे तस्करी नेटवर्क की गहन जांच की मांग की है ताकि इसके पीछे के सभी चेहरों को बेनकाब किया जा सके। डीआरआई के सूत्रों के अनुसार, जब्त की गई मेथामफेटामाइन की खेप का वजन



अल नीनो के खतरे से निपटने के लिए तेलंगाना सरकार ने तैयारी शुरू की, फरवरी 2027 तक प्रभाव चरम पर होने की संभावना है

अल नीनो के खतरे से निपटने के लिए तेलंगाना सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जब फरवरी 2027 में अल नीनो का प्रभाव अपने चरम पर हो, तब इसके असर को कम किया जा सके। इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों के तहत, राज्य के मुख्य सचिव संजय जाजू ने अधिकारियों को अगले 15 से 20 दिनों के भीतर किसानों को किसी भी तरह की पेयजल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, उठाने के निर्देश जारी किए हैं। इन तैयारियों में तालाबों और झीलों के डूब क्षेत्र की जमीन पर चारा उगाना शामिल है, जिसके लिए स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाएगी। पशुपालन विभाग स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस कार्य के लिए मुफ्त बीज उपलब्ध कराएगा। सरकार फसल को बचाने, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्रों के चारे की कमी न होने देने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए हर 15 दिनों में प्रगति की जांच की जाएगी। मुख्य सचिव ने सिंगूर और मंजीरा जलाशयों में घटते जलस्तर को देखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। जलस्तर में गिरावट से कई इलाकों में पेयजल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, जमीन में पानी के स्तर गिरने से किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, भले ही

हैदराबाद: सेना के रिटायर्ड अधिकारी की गोली से मौत, आत्महत्या का शक

► **डेस्क संवाददाता** हैदराबाद के हुसैनियालम थाना क्षेत्र में सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी अलीमुद्दीन की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंच गए, जहां उन्हें शव पर गोली लगने का निशान मिला। पुलिस ने तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद आगे की जानकारी मिलने की उम्मीद है। चारमीनार के एसीपी पी. चंद्रशेखर के अनुसार, पुलिस को संदेह है कि रिटायर्ड अधिकारी ने आत्महत्या की होगी। उन्होंने कहा, "हमें शक है कि उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। हम अभी मामले की जांच कर रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हम बाद में और जानकारी देंगे। " मौत के सटीक कारणों का खुलासा अभी नहीं हो सका है। हुसैनियालम पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और उन परिस्थितियों की गहन जांच कर रही है जिनके कारण यह दुखद घटना हुई। अधिकारी मृतक और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों से भी पृष्ठताछ कर रहे हैं। पुलिस ने अभी तक घटना के सटीक कारणों की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच की जाएगी। घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। फॉरेंसिक टीम मौके से और सबूत जुटाने के लिए जांच कर रही है ताकि घटना के संबंध में किसी भी संदेह को दूर किया जा सके। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या रिटायर्ड अधिकारी किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या या निजी परेशानी से जूझ रहे थे, जो इस कदम के पीछे का कारण हो सकता है।

जांच चल रही है और जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वेसे-वेसे और जानकारी सामने आने की उम्मीद है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस घटना के बारे में बिना पुष्टि के कोई भी जानकारी न फैलाएं, ताकि मृतक के परिवार को अनवश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। मृतक अलीमुद्दीन के परिवार वालों को घटना की सूचना दे दी गई है और पुलिस उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों ने गहरा दुख और हैरानी जताते हुए इस घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सेना के रिटायर्ड अधिकारी की मौत की खबर से स्थानीय समुदाय में गहरा सदमा है। परिवार के सदस्यों और दोस्तों के अनुसार, अलीमुद्दीन एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और किसी भी प्रकार की समस्या से दूर रहते थे। यह घटना सभी के लिए अप्रत्याशित थी। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी। तब तक, सभी कोणों से जांच जारी रहेगी। पुलिस यह सुनिश्चित करने

जनसेना ने जारी की नगर पालिका चुनाव के लिए पहली सूची

► **डेस्क संवाददाता** आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा के बाद जनसेना पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी अध्यक्ष और उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी है। इस सूची में दो नगर निगमों और 12 नगर पालिकाओं के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। यह कदम राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पार्टियों अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रही हैं। नगर निगम चुनावों के लिए जारी सूची में एलुरु से रेड्डी अप्पाला नायडू और विजयवाड़ा से वंगावीती राधा कृष्ण को उम्मीदवार बनाया गया है। ये दोनों ही क्षेत्र पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी पूरी ताकत झोंकेगी। इन नामों के त्दान से स्थानीय स्तर पर चुनावी सगर्मी तेज हो गई है। नगर पालिकाओं के लिए भी पार्टी ने कई उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई है। इनमें अमलपुरम से नल्ला श्रीधर, चिलकलुरिपेट से थोटा राजराजेश्वरी, गोलाप्रोलु से कादरी तम्मय्या नायडू, नररापुरम से कोठापल्ली शेलजा,

दो नगर निगमों और 12 नगर पालिकाओं के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल



निदादवोले से कल्लम ज्योति, पेदाना से मत्ता शिव पावनी, पोटपुरम से डॉ. बीरा विजय शेखर, पुटूर से डीएलुमलाई, सातूर से गोरले विजयकुमारी, समालकोट से पिट्टा जानकी रामा राव, नेनाली से थोटाकुरा वेंकट रमण राव और तिरुवुरु से पी. माधवी शामिल हैं। इन सभी उम्मीदवारों को अपने-अपने क्षेत्रों में जीत दर्ज करने का लक्ष्य दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने 2026 के लिए स्थानीय निकाय और नगरपालिका चुनावों की समय-सारणी जारी कर दी है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी की जाएगी।

अल नीनो के खतरे से निपटने के लिए तेलंगाना सरकार ने तैयारी शुरू की, फरवरी 2027 तक प्रभाव चरम पर होने की संभावना है

अल नीनो के खतरे से निपटने के लिए तेलंगाना सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जब फरवरी 2027 में अल नीनो का प्रभाव अपने चरम पर हो, तब इसके असर को कम किया जा सके। इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों के तहत, राज्य के मुख्य सचिव संजय जाजू ने अधिकारियों को अगले 15 से 20 दिनों के भीतर किसानों को किसी भी तरह की पेयजल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, उठाने के निर्देश जारी किए हैं। इन तैयारियों में तालाबों और झीलों के डूब क्षेत्र की जमीन पर चारा उगाना शामिल है, जिसके लिए स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाएगी। पशुपालन विभाग स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस कार्य के लिए मुफ्त बीज उपलब्ध कराएगा। सरकार फसल को बचाने, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्रों के चारे की कमी न होने देने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए हर 15 दिनों में प्रगति की जांच की जाएगी। मुख्य सचिव ने सिंगूर और मंजीरा जलाशयों में घटते जलस्तर को देखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। जलस्तर में गिरावट से कई इलाकों में पेयजल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, जमीन में पानी के स्तर गिरने से किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, भले ही



बिजली उपलब्ध हो। इससे उनकी फसलों को नुकसान हो सकता है। इन संभावित समस्याओं से निपटने के लिए, कृषि, बिजली और सिंचाई विभागों को मिलकर एक विस्तृत कार्य योजना बनाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, कई जिलों में नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाएगी ताकि वे जमीनी स्तर पर तैयारियों का निरीक्षण कर सकें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने

के लिए समन्वय स्थापित कर सकें। अल नीनो के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे ये कदम दूरदर्शी और महत्वपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के बावजूद, राज्य के नागरिक और पशुधन सुरक्षित रहें और कृषि गतिविधियों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। सरकार का उद्देश्य न केवल वर्तमान संकट से निपटना है, बल्कि भविष्य में ऐसी स्थितियों के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना भी है। राज्य के मुख्य सचिव संजय जाजू ने बताया कि अल नीनो का प्रभाव फरवरी 2027 तक सबसे ज्यादा होने की संभावना है। इस पूर्वानुमान के आधार पर, सरकार ने पहले से ही सक्रिय उपाय करना शुरू कर दिया है।

डीएमके ने सीजेपी को समर्थन दिया, कांग्रेस से दूरी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग



► **स्थानीय रिपोर्टर** चेन्नई। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में सीजेपी को अपना समर्थन दिया है। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, एसआईआर को रद्द करने और मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग की है। स्टालिन की अध्यक्षता में हुई सांसदों की बैठक में कांग्रेस पर आंदोलन का श्रेय लेने का आरोप लगाया गया। डीएमके ने स्पष्ट कर दिया कि वह कांग्रेस के साथ किसी साझा मंच पर नहीं जाएगी। पार्टी ने प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी को निंदा करते हुए सीजेपी को कानूनी सहायता देने की घोषणा भी की है। इस बीच, डीएमके के कांग्रेस और इंडी गठबंधन से दूरी बनाने के बाद क्षेत्रीय दलों के साथ एक नया तीसरा मोर्चा बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, स्टालिन और सीजेपी

संस्थापक अभिजीत दिपके के बीच संभावित मुलाकात से नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। डीएमके ने स्पष्ट किया कि वह कांग्रेस के साथ साझा मंच पर नहीं जाएगी। एसआईआर मुद्दे पर डीएमके का रुख कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकता है, खासकर जब आगामी चुनावों में विपक्षी एकता की बात की जा रही है। डीएमके का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। एमके स्टालिन, जो तमिलनाडु के एक प्रमुख राजनीतिक नेता हैं, ने हमेशा क्षेत्रीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे को मजबूत करने की वकालत की है। एसआईआर का विरोध इसी सिद्धांत का एक हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी का मानना ​​है कि यह केंद्र सरकार को राज्यों के मामलों में अतिक्रमण करने की शक्ति देगा।

प्रधानमंत्री ने ज्योतिर्मयी नायक और अंतरा चक्रवर्ती द्वारा गाए भजन का यूट्यूब लिंक साझा किया

है। मां के तीन नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल और प्रकाशमान हैं, जिनसे निरंतर अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। उनके श्वास छोड़ने से भी अग्नि की भयंकर लपटें उत्सर्जित होती हैं, जो उनके रौद्र रूप का प्रतीक हैं। मां कालरात्रि चतुर्भुजी हैं। उनके बाएं हाथों में खड्ग और वरमुद्रा है, तथा दाहिना हाथ हमेशा अभय मुद्रा (भय दूर करने वाली) और वरद मुद्रा (वरदान देने वाली) में रहता है। यह मुद्राएं भक्तों को सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मां कालरात्रि का वाहन गर्दभ (गधा) है, जो उनकी शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। यद्यपि मां का यह स्वरूप अत्यंत रौद्र और भयानक प्रतीत होता है, परंतु वे अपने भक्तों के सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं। अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करने के कारण ही मां कालरात्रि को 'शुभंकारी' के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम उनके भक्तों के प्रति उनके स्नेह और कल्याणकारी स्वभाव को दर्शाता है। मां कालरात्रि को गुड़ अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि

गुड़ का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करती हैं। यह भोग उनकी कृपा प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। तांत्रिकों, योगियों और साधकों के लिए मां कालरात्रि की उपासना का यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस रात में वे विशेष साधनाएं करते हैं जिससे उन्हें आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है। मां कालरात्रि की उपासना से भक्तों के अंदर अटूट साहस, शक्ति और मानसिक शांति का संचार होता है। यह उपासना उन्हें भय पर विजय पाने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। मां कालरात्रि की पूजा विधि में विशेष मंत्रों का जाप और विशेष प्रकार के प्रसाद का अर्पण शामिल होता है। भक्तजन लाल रंग के वस्त्र धारण कर मां की पूजा करते हैं। मां को लाल पुष्प, विशेषकर गुड़हल का फूल अर्पित किया जाता है। उनके जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता के मार्ग प्रशस्त होते हैं।

आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव: जनसेना ने जारी की पहली सूची, पवन कल्याण ने दी मंजूरी

इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, एपी पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत एक नई ग्रीनफील्ड राजधानी विकसित करने की योजना बनाई गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना और एक आधुनिक प्रशासनिक केंद्र स्थापित करना था। नई राजधानी के विकास के लिए लैंड पुलिंग स्कीम (एलपीएस) के माध्यम से 'अमरावती' को बसाने की योजना बनाई गई। इस योजना के तहत, किसानों से जमीन लेकर उन्हें विकसित राजधानी में हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव था। यह एक अनूठी पहल थी जिसका उद्देश्य विकास में सभी हितधारकों को शामिल करना था, हालांकि इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ भी थीं। यह राजधानी विकास परियोजना राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसे एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इसके पूरा होने से न केवल प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय निकाय चुनावों का शेड्यूल जारी होने के साथ ही, राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, और पार्टियों अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं।



वर्ष 1991 में, अमेरिका मध्य पूर्व में अपने प्रभाव के चरम पर था। इराकी सेनाओं को कुवैत से खदेड़ दिया गया था, सोवियत संघ विघटन के करीब था, और मैड्रिड शांति सम्मेलन की तैयारियाँ चल रही थीं। वाशिंगटन ऐसा प्रतीत होता था कि वह क्षेत्रीय व्यवस्था को आकार देने में सक्षम है। पैंतीस साल बाद, क्या अमेरिका अभी भी क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी दे सकता है? ईरान के साथ युद्ध ने उस क्षमता की सीमाओं को उजागर कर दिया है। जिसे एक छोटा अभियान माना जा रहा था, वह एक महंगा टकराव बन गया है, जो ऊर्जा आपूर्ति, शिपिंग और अमेरिका के खाड़ी सहयोगियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। वाशिंगटन अपनी सैन्य प्रतिबद्धताओं को कम कर सकता है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बदलाव क्षेत्र के प्रमुख सुरक्षा वास्तुकार के रूप में उसकी भूमिका का क्षरण होगा। अमेरिकी शक्ति बनी रहेगी; लेकिन क्षेत्रीय परिणामों को निर्धारित करने की इसकी क्षमता शायद नहीं। यह केवल एक सैन्य बदलाव नहीं, बल्कि एक रणनीतिक बदलाव है। अमेरिकी हस्तक्षेपों का इतिहास इस दुर्दशा को समझाने में मदद करता है। इराक पर आक्रमण ने सद्दाम हुसैन को हटा दिया, लेकिन उसने ईरान के लिए एक प्रमुख प्रतिस्तुलन को भी समाप्त कर दिया, जिससे तेहरान को अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिली। लीबिया और सीरिया में हस्तक्षेप स्थिर राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने में विफल रहे, जबकि यमन संघर्ष ने राजनीतिक परिणाम सुरक्षित करने में सैन्य श्रेष्ठता की सीमाओं को उजागर किया। अरब सरकारों ने भी मिश्र में होन्सी मुबारक के प्रस्थान को संभालने से लेकर अपनी बदलती क्षेत्रीय प्राथमिकताओं तक, वाशिंगटन की संगति पर सवाल उठाया है। ये घटनाएँ भिन्न थीं, लेकिन वे एक सतत समस्या को दर्शाती हैं: सैन्य प्रभुत्व स्वा्यालित रूप से एक स्थायी राजनीतिक समाधान प्रदान नहीं करता है। वाशिंगटन और तेहरान के बीच अंतरिम समझ का टूटना दोनों पक्षों को लाभ की तलाश में छोड़ गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से शिपिंग पर ईरानी दबाव वैश्विक ऊर्जा बाजारों को खतरे में डालता है, जबकि अमेरिकी प्रतिबंध तेहरान के आर्थिक संबंधों को सीमित करने का प्रयास करते हैं। तेल की कीमतें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव का एक साधन बन गई हैं, खासकर नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले। तेहरान यह गणना कर सकता है कि संघर्ष को लंबा खींचने से वाशिंगटन के लिए घरेलू राजनीतिक लागत बढ़ जाएगी। लाल सागर के आसपास अस्थिरता समस्या को और बढ़ा देती है। यमन में हूती की प्रगति और सऊदी क्षेत्र पर हमले खाड़ी के बुनियादी ढांचे और परिवहन नेटवर्क की भेद्यता को रेखांकित करते हैं। राजशाही एक असहज दुविधा का सामना करती हैं: निरंतर संघर्ष से ऊर्जा राजस्व, पर्यटन और निवेश को नुकसान होता है, लेकिन एक तेज अमेरिकी वापसी उन्हें असुरक्षित छोड़ देगी।

इस बीच, वाशिंगटन को अपने आगे के ठिकानों की भेद्यता के मुकाबले क्षेत्रीय ठिकानों को बनाए रखने की लागत का मूल्यांकन करना होगा। विमान वाहक और डिगोए गार्सिया अपनी आगे की उपस्थिति के जोखिमों की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकते। एक कम अमेरिकी भूमिका जरूरी नहीं कि एक स्थिर क्षेत्रीय संतुलन पैदा करे। तीन शक्तियाँ परिणामी स्थान का फायदा उठा सकती हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएँ संगत होने की संभावना नहीं है। ईरान ने दुर्जेय मिसाइल क्षमताएं और क्षेत्र भर में संबद्ध शास्त्र समूहों के नेटवर्क विकसित किए हैं। इसका अस्तित्व इराक, सीरिया और लेबनान को प्रभावित करने की इसकी क्षमता को बनाए रखेगा। 2006 युद्ध के बाद लेबनान में एक कमांडिंग अधिकारी के रूप में मेरे अनुभव ने ईरान के क्षेत्रीय नेटवर्क की गहराई को रेखांकित किया। तेहरान संभवतः उनके पुनर्निर्माण की तलाश करेगा और अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को फिर से जीवित कर सकता है। परमाणु हथियार हासिल करने की दिशा में एक गंभीर कदम से अमेरिकी या इजरायली हस्तक्षेप के नवीनीकरण की संभावना तेज हो जाएगी।

निवेश संधियों का संतुलन: विदेशी निवेश और कर संप्रभुता के बीच

► **प्रिया सिंह** विदेशी निवेश, आर्थिक सफलता का पैमाना माने जाते हैं, और द्विपक्षीय निवेश संधियाँ (बिस्स) निवेशकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संधियाँ एक स्थिर नियामक ढाँचा प्रदान कर निवेशकों की चिंताएँ दूर करती हैं, जिससे अप्रत्याशित लागतों का भय कम होता है। हालाँकि, यही आश्चान्न कई बार निवेशकों को संप्रभु नियामक शक्तियों को सीमित करने के लिए उच्च सुरक्षा मानकों का सहारा लेने की अनुमति दे देते हैं।

केयर्स और वोडाफोन के मामले ऐसे ही उदाहरण थे, जहाँ लेन-देन की विशिष्टताओं ने निवेश के इरादे से परे जाकर निवेशक अधिकार स्थापित कर दिए। कुछ लोग इसे सुरक्षा का मुद्दा मानते हैं, पर जब निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार जैसे मानकों का प्रयोग एक्टरफा होला है, यानी कर आधार के लिए कोई पारस्परिक सुरक्षा न हो, तो स्थिति क्या होती है?

इन संधियों का एक अन्य प्रासंगिक अनुच्छेद विनियोग से संबंधित है। ऐतिहासिक अनुभव, जैसे 1938 में मेक्सिको में तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण, 1959 में क्यूबा द्वारा विदेशी संपत्तियों का अधिग्रहण, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, इस मुद्दे को प्रासंगिक बनाते हैं। चिंताएँ निराधार नहीं हैं, पर क्या ये चिंताएँ



वर्तमान परिदृश्य में भी उत्तनी ही प्रासंगिक हैं?

ऊर्जा आपूर्ति और खनन उद्योग, निवेशक-राज्य विवादों (आईएसडीएस) में एक तिहाई का योगदान करते हैं, इसलिए मानक वैध माने जाते हैं। परंतु, इन सुरक्षा मानकों का विस्तार किताब होना चाहिए, खासकर जब संपत्ति के स्वामित्व में बदलाव के लिए उपलब्ध उपचार नीतिगत संप्रभुता का विकल्प नहीं हो सकता? विडंबना यह है कि जो देश इन मानकों को लागू करते हैं, वे अक्सर कानून के शासन का पालन नहीं करते।

अमेरिका, निवेशक-राज्य विवाद समाधान (आईएसडीएस) में 17.4 प्रतिशत मामलों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके बावजूद, विकासशील देशों को कर जैसे नीतिगत उपायों से द्विपक्षीय निवेश संधि सुरक्षा का विस्तार करना पड़ता है। पिछले एक दशक में, 134 कर-संबंधित आईएसडीएस मामले दर्ज किए गए,



दवाओं की कीमतों में भारी अंतर पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, पूछा कौन कमा रहा है लाभ?

जीवन रक्षक दवाओं की एमआरपी और आपूर्ति मूल्य में भारी अंतर पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

► **राजेश शर्मा** कोलकाता में पेट दर्द का इलाज करा रही एक महिला को अचानक पता चला कि उसे एडवॉर्ड स्ट्रेज का ओवेरियन कैंसर है। उपचार एक कैंसर सेंटर में शुरू होता है। बीमारी से जुझते हुए, मरीज अक्सर खुद को न केवल शारीरिक पीड़ा बल्कि विनाशकारी वित्तीय संकट का सामना करते हुए पाते हैं। बचत खत्म हो जाती है, गहने बेचने पड़ते हैं, और कभी-कभी जमीन या घर गिरवी रखने पड़ते हैं। बच्चों की शिक्षा, शादी के खर्च या भविष्य की सुरक्षा के लिए रखा गया पैसा अस्पताल के काउंटरों पर गायब हो जाता है। इलाज खत्म होने के बाद भी, इस वित्तीय तबाही के घाव आसानी से नहीं भरते। बीमारी सिर्फ शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती; इसका प्रभाव पूरे परिवार के वर्तमान और भविष्य में फैलता है। अक्सर, इस

पीड़ा की सबसे डूर कीमत दवा की कीमत पर लिखी जाती है। यह वास्तविकता विशेष रूप से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज में कठोर हो जाती है। दवा मूल्य निर्धारण पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों ने एक बार फिर इस असहज सच्चाई को सामने लाया है। एक कैंसर दवा कथित तौर पर खुदरा विक्रेताओं को ₹2,700 में आपूर्ति की जा रही है, जबकि इसका अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) ₹29,000 है। दूसरे शब्दों में, आपूर्ति मूल्य और मुद्रित खुदरा मूल्य के बीच दस गुना अंतर है। 29 सितंबर को, जस्टिस विक्रम नाथ और सदीप मेहता की पीठ ने इस भारी अंतर के कारण पर सवाल उठाया और पूछा कि अतिरिक्त राशि से कौन लाभान्वित हो रहा है। पीठ ने स्थिति को 'नरसंहार' भी बताया।

सवाल, इसलिए, सिर्फ एक कैंसर दवा की कीमत का नहीं है। यह दवा बाजार के चरित्र से संबंधित है। जीवन बचाने के लिए आवश्यक उत्पाद की कीमत तय करने के मामले में बाजार की स्वतंत्रता कहाँ समाप्त होनी चाहिए? जब एक मरीज डॉक्टर के पर्चे के साथ फार्मसी काउंटर के सामने खड़ा होता है, तो मोलभाव की गुंजाइश बहुत कम होती है। निर्धारित दवा खरीदनी ही पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में, एक असामान्य मूल्य अंतर केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं रह जाता और यह मानवीय गरिमा का प्रश्न बन जाता है। भारत में दवा की कीमतों को विनियमित करने के लिए ड्रग्स ग्राइड कंट्रोल ऑर्डर, 2013, या डीपीसीओ है। निर्दिष्ट अनुसूचित दवाओं के लिए, सरकार एक निर्धारित अधिकतम मूल्य लागू करती है। हालांकि, इस सूची के



बाहर की कई दवाओं के लिए मूल्य विनियमन तुलनात्मक रूप से सीमित है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, दवा बाजार का एक बड़ा हिस्सा ऐसी 'गैर-

अनुसूचित' दवाओं से बना है। यह काफी अंतर के लिए जगह छोड़ता है। यह ठीक इसी बिंदु पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक समान मूल्य निर्धारण नीति की संभावना

पर केंद्र सरकार से विचार मांगा है। पीठ ने पूछा कि जब आवश्यक दवाओं पर खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन पर पहले से ही एक निर्धारित सीमा मौजूद है, तो अन्य दवाओं के MRP पर समान सिद्धांत क्यों नहीं लागू किया जा सकता। इसने सरकार से दवाओं पर लगभग 16 प्रतिशत का समग्र खुदरा मार्जिन रखने की संभावना पर भी विचार करने को कहा। हालांकि, यह अभी भी अदालत की कार्यवाही के दौरान उठाया गया एक प्रश्न और प्रस्ताव है; कोई नया सार्वभौमिक मूल्य निर्धारण नियम अभी तक लागू नहीं हुआ है। निजी अस्पतालों द्वारा संचालित इन-हाउस फार्मसियों का मुद्दा भी इस बहस से जुड़ा है। अदालत के एमक्ष आरोप लगाए गए हैं कि कुछ कॉर्पोरेट अस्पताल मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर करते हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता: शुल्क प्रदर्शन

► **राजेश शर्मा** अस्पतालों और क्लीनिकों में इलाज के खर्च को लेकर पारदर्शिता की कमी की शिकायतें आम रही हैं। यह समस्या सिर्फ महंगे अस्पतालों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे क्लीनिकों और सरकारी अस्पतालों में भी देखी जाती है, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बीमारी से बड़ी आर्थिक चिंता खड़ी हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सेवाओं के शुल्क प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएँ। यह कदम निश्चित रूप से व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और मरीज-अनुकूल बनाने की दिशा में एक स्वागत योग्य पहल है। अक्सर इलाज के लिए आने वाले मरीजों को उपचार के खर्च की स्पष्ट जानकारी नहीं होती। परामर्श शुल्क, जांच, इलाज की प्रक्रियाओं और अस्पताल की सुविधाओं के बारे में सटीक जानकारी होने से मरीजों को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है और वे अचानक आने वाले वित्तीय बोझ से बच सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुख्य सचिवों को इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दूरअसल, क्लिनिकल, एस्टेब्लिशमेंट्स (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और संबंधित नियम 2012 के तहत अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी सेवाओं और सुविधाओं के शुल्क ऐसी जगह प्रदर्शित करें जहां मरीज और उनके परिजन आसानी से देख सकें। यह हमारे दोनों में उपलब्ध होनी चाहिए। हालांकि,

कुछ सरकारी और निजी अस्पतालों के संचालक शुल्क सीमा तय करने से उपचार की गुणवत्ता प्रभावित होने की दलील देते हैं। कई निजी अस्पताल और क्लीनिक संचालक इन निर्देशों को लागू करने में विभिन्न प्रकार के किंतु-परंतु निभाते हैं। उनकी चिंता है कि इन नियमों से उपचार की आर्थिक व्यवहार्यता कमजोर हो सकती है, जिससे परिचालन लागत, बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता के अंतर को नजरअंदाज किया जा सकता है। इन चिंताओं पर करें कि स्वास्थ्य सेवाओं के शुल्क प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएँ। यह कदम निश्चित रूप से व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और मरीज-अनुकूल बनाने की दिशा में एक स्वागत योग्य पहल है। अक्सर इलाज के लिए आने वाले मरीजों को उपचार के खर्च की स्पष्ट जानकारी नहीं होती। परामर्श शुल्क, जांच, इलाज की प्रक्रियाओं और अस्पताल की सुविधाओं के बारे में सटीक जानकारी होने से मरीजों को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है और वे अचानक आने वाले वित्तीय बोझ से बच सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुख्य सचिवों को इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दूरअसल, क्लिनिकल, एस्टेब्लिशमेंट्स (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और संबंधित नियम 2012 के तहत अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी सेवाओं और सुविधाओं के शुल्क ऐसी जगह प्रदर्शित करें जहां मरीज और उनके परिजन आसानी से देख सकें। यह हमारे दोनों में उपलब्ध होनी चाहिए। हालांकि,

एससी/ओबीसी के मतांतरित होने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ने मतांतरितों को आरक्षण से किया वंचित

► **सुनीता वर्मा** धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण का लाभ न मिलने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तमिलनाडु सरकार की उस नीति को चुनौती दी है, जिसके तहत धर्मांतरित लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलता था। यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने और आरक्षित वर्गों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि कुछ लोग एससी या ओबीसी वर्ग से होने के कारण आरक्षण का लाभ उठाते थे, लेकिन इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी वे इस लाभ को जारी रखना चाहते थे। इस प्रवृत्ति ने न केवल आरक्षण के मूल उद्देश्य को कमजोर किया, बल्कि सनातन धर्म के भीतर सामाजिक कोट की व्यवस्था को भी प्रश्नचिह्न लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और वह अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो वह आरक्षण का लाभ पाने का हकदार नहीं रहेगा। यह निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती फैसले के अनुरूप है, जिसे तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

सरकार की मंशा उस नियम को बनाए रखने की थी, जिसके अनुसार एससी या ओबीसी समुदाय के लोग, भले ही वे इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लें, तब भी आरक्षण के लाभ प्राप्त करते रह सकते थे। यह नीति न केवल सनातन परिवार के आरक्षित वर्गों के अधिकारों में कटौती करती थी, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से धर्मांतरण को भी बढ़ावा देती थी। यह एक कड़वी सच्चाई है कि एससी या ओबीसी वर्ग के कई हिंदू, सिख या बौद्ध अपने धर्म का त्याग कर देते हैं और फिर यह मांग करते हैं कि धर्मांतरण के बाद भी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इस तरह की मांगों का समर्थन कई मुस्लिम और ईसाई संगठन भी करते हैं। विडंबना यह है कि वे ऐसे दावों के साथ अपने ही उन तर्कों को खोखला साबित करते हैं, जिनमें वे कहते हैं कि उनके धर्मों में जाति व्यवस्था नहीं है या जातिगत

भेदभाव नहीं होता। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसी तरह के प्रलोभनों के आधार पर वे गरीब और अशिक्षित हिंदुओं, सिखों आदि को धर्मांतरित होने के लिए लुभाते हैं। वास्तविकता यह है कि एससी या ओबीसी वर्ग के लोग जब धर्मांतरण कर नए पंथों में शामिल हो जाते हैं, तब भी उन्हें अक्सर जातिगत भेदभाव और वैमनस्य का सामना करना पड़ता है। इसी कारण दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों के अपने अलग संगठन बने हुए हैं, जो इस भेदभाव को खिलाफ आवाज उठाते हैं। यह दर्शाता है कि धर्म परिवर्तन करने से सामाजिक असमानता और भेदभाव समाप्त नहीं होते, बल्कि वे नए रूप में जारी रह सकते हैं। तमिलनाडु सरकार का नियम केवल धर्मांतरण को प्रोत्साहन देने वाला ही नहीं था, बल्कि यह एससी और ओबीसी वर्गों के अधिकारों पर भी कुठाराघात कर रहा था। इसके अतिरिक्त, यह भी एक गंभीर समस्या थी कि हिंदू धर्म त्यागने वाले एससी या ओबीसी वर्ग के लोग आरक्षण के साथ-साथ अल्पसंख्यकों को मिलने वाले अन्य लाभों का भी दोहन कर रहे थे।

इस दोहरे लाभ का आकर्षण उन लोगों के लिए एक बड़ा प्रलोभन था जो छल-छद्म और लालच के सहारे धर्मांतरण कराते थे। इसका सबसे अधिक नुकसान हिंदू समाज को उठाना पड़ता था, खासकर इसलिए क्योंकि सिखों और बौद्धों के अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि हिंदू समाज, विशेष रूप से, ईसाई और मुस्लिम संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कपटपूर्ण और लालच-आधारित धर्मांतरण अभियानों का प्रमुख लक्ष्य रहा है। भले ही विभिन्न राज्य सरकारें छल-कपट से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए लगातार कानून बना रही हैं या मौजूदा कानूनों को और कड़ा कर रही हैं, लेकिन धर्मांतरण की यह प्रक्रिया रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसका मूल कारण धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किस हद तक हो रहा है, यह तमिलनाडु सरकार के उस नियम से स्पष्ट होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। इस नियम के तहत, अनुसूचित जाति और

सरुदी अरब में हिंदू इंजीनियर को मृत्युदंड: भारतीय नेताओं की चुप्पी चिंताजनक

► **विकास पांडेय** श्रीलंकाई हिंदू इंजीनियर सिवारसा अंनोजन को सरुदी अरब में मृत्युदंड की सजा सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी के कारण सुनाई गई है। यह घटना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन भारतीय नेताओं और संगठनों की ओर से आध्यर्जनक चुप्पी देखी जा रही है। सिवारसा एक बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। एक तमिल मुस्लिम के साथ विवाद के दौरान की गई उनकी टिप्पणी पर यह फैसला आया है। यह मामला मानवतावादी दृष्टिकोण से चिंताजनक है, क्योंकि यह एक्टरफा इस्लामी कानूनों को थोपने वाले शासकों की ओर से किसी भी व्यक्ति के प्रति कठोर कार्रवाई का उदाहरण है। घटना की शुरुआत 27 जून को श्रीलंका के कटरगामा में भगवान मुस्लम की तीर्थयात्रा के दौरान हुई। एक मुस्लिम व्यक्ति ने तीर्थयात्रियों के पीछे चल रहे कुत्ते को लात मारते हुए एक रील बनाई। इसके जवाब में, फेसबुक पर एक टिप्पणी में किसी मुसलमान ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बात कही। सिवारसा ने तमिल में फैमबर मोहम्मद पर एक टिप्पणी करके इसका उत्तर दिया। हालांकि, उन्होंने तुरंत अपनी टिप्पणी डिलीट कर दी और माफी भी मांगी। लेकिन किसी ने उस टिप्पणी का स्क्रीनशॉट लेकर सिवारसा की कंपनी के सऊदी मालिक को भेज दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शुरूआत में सिवारसा को पांच साल की जेल और 30 लाख सरुदी रियाल के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

परंतु, गत 17 सितंबर को अपीलीय अदालत ने शरीयत कानून के तहत उनकी सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड कर दिया। यह फैसला कई गंभीर सवाल खड़े करता है, जिस पर सभी मानवतावादी लोगों, विशेषकर हिंदू नेताओं और बुद्धिजीवियों को ध्यान देना चाहिए। यह देखा गया है कि इस्लामी शासक किसी भी विचारधारा के हिंदू में फर्क नहीं करते, जैसा कि कश्मीर में भी हाल ही में हुआ। जिहाद और शरीयत ने बिना किसी पक्षपात के हिंदुओं का सफाया किया या उन्हें खदेड़ दिया। सऊदी अरब में सिवारसा की घोगणा कोई बाहरी या अप्रासंगिक घटना नहीं है। भारत में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, जिन पर भारतीय राजनीतिक और बौद्धिक वर्ग की चुनिंदा चुप्पी और शोर-शराबा एक्टरफा विशेषाधिकार और जुल्म को बढ़ावा देता है। इस्लामी विवादों के मामले अक्सर अंतरराष्ट्रीय रंगत रखते हैं और किसी देश की सीमाओं, संविधान या नैतिकता को नहीं मानते। यह निराशाजनक है कि किसी भी भारतीय हिंदू नेता, संगठन या प्रमुख बौद्धिक ने सिवारसा को मृत्युदंड सुनाए जाने पर सऊदी अरब से कुछ कहने या अपील करने का प्रयास नहीं किया। यहां तक ​​​​कि सऊदी दूतावास जाकर राजदूत को एक जापन या निवेदन देना भी एक प्रभावी कदम हो सकता था, लेकिन भारत में किसी को यह सूझता भी नहीं। कई हिंदुओं ने भी भगवान शिव के अपमान पर प्रतिक्रिया में कुछ बोल देने वाले हिंदू को मृत्युदंड दिए जाने पर एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। यह हिंदू नेताओं की दूरदर्शिता की कमी को

मुफ्त इलाज से गरीबी और कर्ज के दुष्प्रक्र से बचाव, लाखों को लाभ आयुष्मान योजना: गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक नीति



► **संजय मिश्रा** आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए सिर्फ स्वास्थ्य बीमा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सामाजिक नीति के रूप में उभरी है। यह योजना न केवल गरीब बीमारियों के मुफ्त इलाज की सुविधा देती है, बल्कि लोगों को गरीबी और कर्ज के ऐसे दुष्प्रक्र से भी बाहर निकालती है, जिसमें वे अक्सर फंस जाते हैं। यह योजना सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिससे वंचित और जरूरतमंद वर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, ने भारतीय समाज में स्वास्थ्य और गरीबी के बीच गहरे संबंध को समझा है। यह योजना निर्धन, पिछड़े और जरूरतमंद लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इसका उद्देश्य केवल स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना नहीं है, बल्कि वंचितों को गरिमापूर्ण जीवन जीने और समान अवसर प्राप्त करने में मदद करना भी है। यह योजना सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करती है। सीमांत समाजों में इस योजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि यह वंचित वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। फील्ड वर्क के दौरान यह देखा गया कि यह योजना न केवल जीवन रक्षा कर रही है, बल्कि लोगों को कर्ज और गरीबी के जाल से भी बाहर निकाल रही है। गंभीर बीमारियों के मुफ्त उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण व्यक्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे उनका पारिवारिक जीवन सुगम हुआ है और वे अपने सामाजिक-आर्थिक दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हुए हैं। आयुष्मान योजना के माध्यम से लाभार्थी उचित स्वास्थ्य लाभ के बाद अपने सामाजिक-आर्थिक जीवन में पुनः सक्रिय हो पाते हैं और एक बेहतर जीवन जी पाते हैं। इस प्रकार, यह योजना स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करके व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी दोनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह योजना सामाजिक समावेशन और स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को कम करने का एक प्रभावी माध्यम बनी है। भारतीय समाज, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां संरचनात्मक असमानताएं व्यापक हैं, यह योजना अस्पतालों की उपलब्धता, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक भेदभाव से परे कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है।

गंभीर बीमारियों के मुफ्त उपचार से वंचित समुदायों के जीवन में आशा की एक नई

किरण जगी है। भारत में गरीबी की दूर धीरे-धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी भी 12.4 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। इस गरीबी में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च की एक बड़ी भूमिका है। भारत में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल व्यय का 62.6 प्रतिशत लोग अपनी जेब से वहन करते हैं, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है। स्वास्थ्य पर यह अत्यधिक जेब खर्च भारत में गरीबी को बढ़ाने में एक प्रमुख कारक रहा है। जब कोई गरीब व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो उसे अक्सर सूखों-सों से कर्ज लेना पड़ता है। समाज के वंचित वर्ग के लोग बड़ी संख्या में अनौपचारिक माध्यमों से कर्ज लेते हैं। नेशनल सैपल सर्वे आर्गनाइजेशन के अनुसार, भारत में गरीबी में लगभग 2.61 प्रतिशत की वृद्धि स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के कारण होती है। इलाज के लिए लिया गया कर्ज चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता जाता है। यदि परिवार का कोई सदस्य लंबे समय तक बीमार रहता है, तो आय सृजन न होने के कारण वह परिवार और गहरा गरीबी में डूब जाता है। भारत सरकार ने इन गंभीर स्थितियों को समझते हुए ही आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत, हर गरीब परिवार को साल भर में सरकारी और सूचीबद्ध अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। अब तक 12.69 करोड़ से अधिक लोगों को अस्पतालों में भर्ती कर 1.92 लाख करोड़ रुपये से अधिक का इलाज मुहैया कराया जा चुका है। इस योजना के तहत भारत में अब तक कुल 42.31 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 49 प्रतिशत कार्ड महिलाओं और 51 प्रतिशत कार्ड पुरुषों के नाम पर बनाए गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत 5.59 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जो इस योजना की व्यापक पहुंच को दर्शाता है। एक गांव की बूढ़ी महिला ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया, 'जब मुझे पेट की बीमारी हुई तो लगा अब नहीं बचेगा। गरीब के पास अस्पताल जाने की हिम्मत कहां। भेटे को न जाने कहां से आयुष्मान योजना के बारे पता चला। उसे हासिल कर अस्पताल गए तो इलाज हुआ। ' यह अनुभव दर्शाता है कि कैसे यह योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुरक्षा पहुंचा रही है। जन स्वास्थ्य की इस योजना ने गांवों और शहरों की झुग्गी बस्तियों तक अपने प्रभाव को फैलाया है। इसने समाज के एक बड़े हिस्से को निर्धनता से मुक्त होने में मदद की है, और उन्हें यह अहसास कराया है कि सरकार उनकी जरूरतों को समझती है और उनके प्रति संवेदनशील है, जिससे उनमें एक नई आशा और आत्मविश्वास का संचार

अब्दु रोजिक का दर्द: सगाई टूटना थी जिंदगी की बड़ी भूल



► **ब्यूरो प्रतिनिधि** रियलिटी शो 'बिग बॉस 16' से मशहूर हुए अब्दु रोजिक ने अपनी सगाई टूटने पर पहली बार खुलकर बात की है। उन्होंने माना कि सगाई की खबर को सोशल मीडिया पर साझा करना उनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी भूल थी। अब्दु रोजिक जल्द ही हॉरर शॉर्ट फिल्म 'कॉन्जूर: द रील फाइल्स' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। मिड डे से बातचीत में अब्दु ने कहा कि वे फैंस को परिवार मानते हैं और उनकी खुशी साझा करना चाहते थे, लेकिन कई लोगों ने नकारात्मकता फैलाई।

नेहा धूपिया को शाहरुख खान की फिल्म ठुकराने का अफसोस



► **चरिष्ठ प्रतिनिधि** अभिनेत्री नेहा धूपिया ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'डॉट बी शाय' के बाद एक बात पर गहरा अफसोस जताया है। उन्होंने उन दो बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया जिन्हें करने की उनकी तीव्र इच्छा थी, लेकिन जिन्हें वह ठुकरा चुकी थीं। नेहा ने बताया कि उन्होंने शाहरुख खान अभिनीत 2007 की स्पोर्ट्स ड्रामा 'चक दे! इंडिया' और 'ऑपरेशन सफेद सागर' नाम की एक सीरीज को करने से इनकार कर दिया था, और अब उन्हें इस फैसले पर पछतावा है। यह खुलासा उन्होंने अपने लोकप्रिय चैट शो 'डबल डेट' के दौरान किया, जहां उन्होंने अपने करियर के उन महत्वपूर्ण मौकों पर बात की जो उनके हाथ से निकल गए। नेहा धूपिया ने अपने शो 'डबल डेट' में कहा, 'कभी-कभी, जब आप उन मौकों को याद करते हैं जिन्हें आपने ठुकरा दिया था, तो आपको एहसास होता है कि आपने क्या खो दिया।' उन्होंने आगे कहा, 'चक दे! इंडिया' और 'ऑपरेशन सफेद सागर' ऐसे ही दो बड़े मौके थे जो मेरे साथ रह गए। मैं हमेशा से एक अच्छी स्पोर्ट्स फिल्म और एक अच्छी मिलिट्री फिल्म करना चाहती थी, मगर ये दो बड़े मौके मेरे हाथ से निकल गए, जिसका मुझे आज

शाहरुख ने रोमांस का स्टैंडर्ड बढ़ाया: मृणाल

अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने बताया कि कैसे शाहरुख खान के रोमांटिक किरदारों ने बॉलीवुड में प्यार को लेकर उनकी सोच को नया रूप दिया है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "शाहरुख खान मेरी जिंदगी में नहीं हैं, यह बात मेरा दिल तोड़ देती है।" एक्ट्रेस के मुताबिक, शाहरुख ने रोमांस के स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे कर दिए हैं कि उन्हें अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो पढ़ें पर उनके रोमांटिक अंदाज की बराबरी कर सके। मृणाल ने कहा, "मुझे शाहरुख सर से बेपनाह प्यार है।" उन्होंने आगे कहा कि शाहरुख खान ने पढ़ें पर जितने भी किरदार निभाए हैं, वे सभी कमाल के हैं। एक्ट्रेस को अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो शाहरुख खान जितना रोमांटिक हो।

राधिका अंबानी ने स्टाफ संग मनाया जन्मदिन, सादी ड्रेस में दिखीं खूबसूरत

► **प्रतिनिधि डेस्क** राधिका अंबानी ने 16 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर, उनके घर और ऑफिस के स्टाफ सदस्यों ने एक खास सरप्राइज की योजना बनाई। राधिका, जो अनंत अंबानी की पत्नी हैं, अपनी सादगी और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने इस खास दिन पर एक बेहद खूबसूरत और किफायती ड्रेस पहनी थी, जिसकी कीमत जानकर लोग हैरान रह गए। स्टाफ द्वारा आयोजित फूलों से सजे केक और सजावट को देखकर राधिका मर्चेट बेहद खुश हुईं। उन्होंने स्टाफ मेंबरस द्वारा अपने रास्ते में सजाए गए ताजे फूलों और फूलों की बारिश का आनंद लिया। इसके अलावा, स्टाफ ने फूल और मोमबत्तियों से सजा एक शानदार केक भी तैयार किया, जिसे राधिका ने सबके साथ मिलकर काटा। इस सरप्राइज ने राधिका को बेहद उत्साहित और प्रसन्न कर दिया, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। राधिका मर्चेट ने अपने जन्मदिन के जश्न के लिए ब्राउन और काइट पोलका डॉट वाली एक स्लीवलेस ड्रेस चुनी, जिसमें सफेद लेस की बारीक डिटेिलिंग थी। यह

राधिका-कीर्ति की 'अक्का' का टीज़र जारी, 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज

► **डेस्क प्रतिनिधि** अभिनेत्री राधिका आटे और कीर्ति सुरेश जल्द ही 'अक्का' नामक आगामी सीरीज में साथ नजर आएंगी। यह सीरीज 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें गैंगस्टर ड्रामा देखने को मिलेगा। निर्माताओं ने शनिवार को कीर्ति के जन्मदिन के अवसर पर इस सीरीज का टीज़र जारी किया, साथ ही सीरीज का रिलीज की तारीख भी घोषित की। 'अक्का' अक्टूबर में दर्शकों के बीच आएगी। टीज़र में कीर्ति सुरेश भवानी की भूमिका में और राधिका आटे रुद्रा के किरदार में दिखाई दे रही हैं। पेरनुरू नामक स्थान पर इन दोनों पात्रों का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन उनके अलग-अलग विचारों और हितों के टकराव से संघर्ष पैदा होने की संभावना है। धर्मराज शेट्टी 'अक्का' सीरीज के साथ निर्देशन की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। उन्होंने ही इस सीरीज की पटकथा भी लिखी है। यह सीरीज पेरनुरू राज्य की कहानी कहती है, जिसे पीढ़ियों से महिलाओं ने स्थापित किया है, संभाला है और सुरक्षित रखा है। कहानी परंपरा, सत्ता संघर्ष और

प्रतिस्पर्धा के इर्द-गिर्द बुनी गई है। यशराज प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित यह सीरीज 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। कीर्ति ने अपने जन्मदिन पर सीरीज के बारे में बात करते हुए कहा कि 'अक्का' का टीज़र जारी होने से उनका जन्मदिन और भी खास हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 'भवानी' का किरदार उनके द्वारा निभाई गई अब तक की सबसे अलग और यादगार भूमिकाओं में से एक है। कीर्ति ने कहा, "हर साल दर्शकों से मिलने वाला प्यार इस दिन को मेरे लिए बहुत खास बना देता है। मेरे दिल के करीब 'अक्का' सीरीज का टीज़र जारी करके जन्मदिन मनाना मेरे लिए बहुत खास बात है। भवानी मेरे करियर की सबसे अलग और यादगार भूमिकाओं में से एक है।" राधिका आटे ने कहा, "कीर्ति के जन्मदिन पर 'अक्का' सीरीज की रिलीज की तारीख और टीज़र का जारी होना एक बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि यह साल हमारे लिए



प्रकृति और उनके अलग-अलग विचारों से उत्पन्न होने वाला संघर्ष मुझे इस सीरीज की ओर आकर्षित करता है।

माथे पर तिलक से इनकार पर फराह खान को नर्टिजन्स की आलोचना झेलनी पड़ी फराह खान ने तिलक से किया इनकार

बॉलीवुड की जानी-मानी निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह खान एक कार्यक्रम के दौरान माथे पर तिलक लगाने से इनकार करने के बाद सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का शिकार हो रही हैं। वायरल हो रहे एक वीडियो में, एक महिला फराह खान के माथे पर तिलक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फराह विनम्रता से मना कर देती हैं और इसके बजाय अपने हाथ पर तिलक लगाने का अनुरोध करती हैं। यह घटना ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गई है, जिसमें कई लोगों ने उनके इस कदम पर नाराजगी जताई है। कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने सार्वजनिक कार्यक्रम में पारंपरिक स्वागत को स्वीकार करने से इनकार करने पर असंतोष व्यक्त किया है। उनका तर्क है कि फराह खान को तिलक



स्वीकार कर लेना चाहिए था। इस वीडियो के व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद, कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया। एक एक्स (पूर्व में ट्विटर) उपयोगकर्ता ने लिखा कि

रजनीकांत की 'जेलर 2' ने दूसरे दिन भी मचाया धमाल, 'नई नवेली' और 'प्रहार' जैसी नई फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल

► **ब्यूरो संवाददाता** रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी और शानदार शुरुआत की। ओपनिंग डे पर इसने 59.70 करोड़ रुपये की कमाई की। हालांकि, शुक्रवार को दूसरे दिन इसकी कमाई में गिरावट आई और इसने 35.60 करोड़ रुपये कमाए। इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 95.94 करोड़ रुपये हो चुका है। वहीं, वर्ल्डवाइड यह 200 करोड़ क्लब का हिस्सा बन गई है, जिसका कुल कलेक्शन 209.10 करोड़ रुपये हो चुका है। विजय

जेलर 2: 3 दिन में ₹200 करोड़ पार, विश्वव्यापी कमाई ₹213.65 करोड़

► **न्यूज प्रतिनिधि** रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' 2 ने नवरात्र के दौरान सिनेमाघरों में दस्तक दी। शनिवार के कलेक्शन में गिरावट के बावजूद, एक्शन सीक्वल ने तीन दिनों में दुनिया भर में ₹200 करोड़ का नेट आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म के तीसरे दिन की कमाई और क्षेत्रीय प्रदर्शन पर एक नज़र डालते हैं। निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार द्वारा निर्देशित 'जेलर' 2 ने पहले दिन भारत में ₹59.70 करोड़ नेट की कमाई की, जो 16,599 शो से आई थी। दूसरे दिन फिल्म ने ₹37.10 करोड़ की कमाई की, जो 13,157 शो से थी। सैकनलिक के अनुसार, 'जेलर' 2 ने पहले दो दिनों में ₹213.65 करोड़

की विश्वव्यापी कमाई की, जिसमें ₹100 करोड़ विदेशी बाजारों से शामिल थे। शनिवार (तीसरे दिन) को ₹12.35 करोड़ नेट जोड़े गए, जिससे भारत में कुल नेट कलेक्शन ₹128.22 करोड़ हो गया। फिल्म का भारत में सकल कलेक्शन अब तक ₹109.15 करोड़ है। तीसरे दिन, 'जेलर' 2 भारत में 5,674 शो में दिखाई गई।

बिग बॉस 20: लव गिल से झगड़े पर सलमान ने आसिफ खान को लगाई



► **स्थानीय रिपोर्टर** रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के 'वीकएंड का वार' एपिसोड में होस्ट सलमान खान एक बार फिर कंटेस्टेंट आसिफ खान की क्लास लगाएंगे। यह सब आसिफ और लव गिल के बीच हुई तीखी बहस और झगड़े के बाद हो रहा है। सलमान ने आसिफ को न सिर्फ उनकी गलती का अहसास कराया, बल्कि उन्हें बुरी तरह डांटा भी। इस घटनाक्रम के दौरान लव गिल रोती हुई नजर आई, जिससे माहौल और भी गंभीर हो गया। सलमान खान ने आसिफ से लव गिल के नकुल के पास जाने पर आपत्ति जताने को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, 'लव जब नकुल के पास चली गई तो तुन्हें क्यों एतराज हुआ? तुम्हारा क्या लेना-देना भाई। क्या यह तुम्हारी घरवाली है? तुम्हारी बहन है कि क्या है?' इस पर आसिफ ने सफाई देते हुए कहा कि लव का वॉल्यूम हर समय यहाँ रहता है। सलमान के सवाल- जवाब के बीच लव गिल भावुक हो गई और रोते हुए बोलीं कि आसिफ हर बात पर कहते हैं कि वह चापलूसी कर रही है और गंवार है। इस पर आसिफ ने लव से कहा कि वह उनसे ज्यादा चिल्ला रही थीं। लेकिन सलमान ने आसिफ की बात को खारिज करते हुए कहा, 'यह चिल्ला नहीं रही। चिल्ला आप रहे थे। रुड आप थे। बदमाजी आप थे। मैंने पूरा एपिसोड देखा। जिस हिस्से से आपने बात की, मुझे नहीं लगता कि वह कूल था।' लव गिल और आसिफ खान के बीच यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब बीते दिनों नकुल धुल के हाथपाई मामले को लेकर घर दो हिस्सों में बंट गया था। इस बीच लव गिल ने नकुल से बात करने की कोशिश की। घर के बाकी सदस्यों को यह देखकर अजीब लगा। आसिफ खान ने भी लव गिल को टोका और कहा कि उन्हें नकुल के साथ नहीं बैठना चाहिए, यह गलत बात है। आसिफ के इस बयान पर लव गिल ने आपत्ति जताई और कहा कि कोई उन्हें यह न बताए कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद दोनों के बीच काफी तीखी बहस हुई, जिसकी वजह से सलमान खान को बीच में आना पड़ा। सलमान के कड़े रूख को देखते हुए आसिफ को अपनी गलती का अहसास हुआ। एक तरफ जहाँ सलमान खान ने अमेरिकी खान की जमकर क्लास लगाई, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कनिका और यंग को उनकी समझदारी के लिए शाबाशी दी। सलमान ने सभी घरवालों से कहा, 'यह मेंटल स्ट्रेंथ और रणनीति का शो है। हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस है। गुस्सा होना जरूरी है, लेकिन गुस्सा और टेम्पर में फर्क है। ऊपर वाले ने दिमाग दिया है सोचने के लिए। सही चीजों के लिए उसका इस्तेमाल करो।' सलमान ने विशेष रूप से यंग की तारीफ करते हुए कहा, 'यंग ने सबसे ज्यादा लॉजिक की बात की, क्योंकि उसने यह लाइफ देखी है। हैट्स ऑफ यंग'। इसके बाद सलमान ने कनिका से कहा, 'कनिका आपने भी कमाल किया। आप अपने ग्राउंड पर रहें। इस हफ्ते का मेरा काम आपने कर दिया।

एजाज खान का इमरान खान की नागरिकता और स्टारलिक पर बयान, राष्ट्रीय सुरक्षा पर उठाए सवाल

► **ब्यूरो प्रतिनिधि** अभिनेता एजाज खान ने पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की अमेरिकी नागरिकता और हालिया विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। एजाज खान का दावा है कि अगर इमरान खान के पास भारतीय पासपोर्ट होता और वह प्रदर्शन में शामिल होते, तो उन्हें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अमेरिकी नागरिक होने के नाते यह मामला अलग है। उन्होंने स्टारलिक और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए और इस पूरे मुद्दे को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। एजाज खान ने कहा कि उन्हें हाल ही में इमरान खान की अमेरिकी नागरिकता के बारे में पता चला है और अब वह उन्हें अमेरिकी नागरिक के तौर पर ही देखेंगे। इस दौरान उन्होंने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिक का भी जिक्र किया। एजाज ने स्टारलिक की तकनीक और उससे जुड़ी कंपनियों के अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से संबंधों पर चिंता जताई। उन्होंने विशेष रूप से 'स्टारशील्ड' का नाम लेते हुए दावा किया कि यह कंपनी अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के लिए काम करती है और जासूसी से जुड़ी कंपनियों को समर्थन देती है। एजाज खान ने आरोप लगाया कि ऐसी कंपनियां दुनिया भर के बड़े कारोबारियों, पुलिस अधिकारियों और नेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उन्होंने भारत में स्टारलिक की संभावित उपस्थिति पर भी सवाल उठाया और पूछा कि यह कंपनी देश में आकर क्या करेगी। इस संदर्भ में, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र करते हुए कहा, "नरेंद्र मोदी जी कोई दुश्मन नहीं हैं।" एजाज खान के बयान ने इमरान खान की नागरिकता, विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी और स्टारलिक को लेकर उनकी चिंताएं प्रमुखता से शामिल रहीं। यह पूरा मामला 10 अक्टूबर 2026 का है, जब इमरान खान मुंबई के अगास्ट क्रांति मैदान में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त नानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करना था। रिपोर्टों के अनुसार, इमरान खान को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। हालांकि, उन्हें उसी दिन रिहा कर दिया गया था। इस घटना ने इमरान खान की सार्वजनिक गतिविधियों और उनकी नागरिकता को लेकर नई बहस छेड़ दी है, खासकर जब इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक मुद्दों से जोड़ा जा रहा है। एजाज खान द्वारा लगाए गए आरोपों में स्टारलिक और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के बीच कथित संबंध एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उनका कहना है कि स्टारशील्ड जैसी कंपनियां, जो सीआईए से जुड़ी हुई मानी जाती हैं, जासूसी और ब्लैकमेलिंग जैसी गतिविधियों में लिप्त हो सकती हैं। यह आरोप वैश्विक स्तर पर बड़े नामों को प्रभावित कर सकता है, जिसमें व्यवसायी, पुलिस अधिकारी और राजनेता शामिल हैं। भारत में स्टारलिक के प्रवेश को लेकर एजाज खान की चिंताएं राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। उनका प्रश्न है कि क्या इस तरह की विदेशी तकनीक और कंपनियां देश के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं।

